



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 353] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 26, 1990/आषाढ़ 5, 1912  
No. 353] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 26, 1990/ASADHA 5, 1912

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

---

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 1990

का.प्र. 510(प्र) :—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि एकल सचस्यीय जांच  
आयोग अर्थात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री कुलदीप सिंह जिन्हें बंगलौर  
विकास प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य भाग्य हाऊसिंग एसोसिएशन (कर्नाटक) नाम की प्राइवेट

लिमिटेड कम्पनी को होसूर-सरजापुर रोड (कर्नाटक) में 110 एकड़ भूमि के स्थानांतरण के प्रस्ताव तथा मैसर्स नारायणस्वामी एण्ड सन्स, साउथ एण्ड रोड, वासवानगुडो, बंगलौर, जिनका 886/4, लक्ष्मीपुरम, मैसूर में पंजीकृत कार्यालय है, द्वारा मैसर्स रेवाजीत लि. तथा डब्ल्यू.सी., 594-V सेन, 11वां फ़ास, सदाशिव नगर, बंगलौर के नाम सर्वे संख्या 6/1 तथा 6/2, बसहिल्ला गाँव, बंगलौर में स्थित 5 एकड़ और 5 गुंटा (लगभग 22.622 वर्ग मीटर) भूमि को दिनांक 30-9-87 के विलेख द्वारा बेचने के एक लोक महत्व के सुनिश्चित मामले का आदेश देने के लिए भारत सरकार, कानून, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कानून और प्रशिक्षण विभाग) को दिनांक 28 जून, 1989 को अधिसूचना सं. आदेश संख्या 492 के अधीन नियुक्त किया जा गया था, बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।

2. अतः अब जोंच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा तथा न्यायमूर्ति श्री कुलवीर सिंह उक्त आयोग के सदस्य का पद तारीख 26-6-1990 को छोड़ देंगे।

[संख्या 415/8/89-ए.पी.पी.-IV]

डी. पी. बागची,  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES  
AND PENSIONS  
(Department of Personnel & Training)  
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 1990

S.O. 510(E).—Whereas the Central Government is of opinion that the continued existence of the Commission of Inquiry consisting of single member, namely Shri Justice Kuldip Singh, a Judge of the Supreme Court, which was appointed under the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) No. S.O. 492(E) dated the 28th June 1989 to inquire into a definite matter of public importance, namely the proposal to transfer 110 acres of land in the Hosur-Sarjapur Road (Karnataka) by the Bangalore Development Authority to the Non-Resident Indians Housing Association (Karnataka), a Private limited company

and the sale by Messrs Narayanswamy & Sons, South End Road, Basavangudi, Bangalore, having their registered office at 886/4, Lakshmipuram, Mysore, by a deed purported to be executed on 30-9-1987 of 5 acres and 24 guntas (approximately 22,622 square metres) of land, situated in Survey No. 6/1 and 6/2 of Dasarhalli Village, Bangalore, in favour of Messrs Revajeetu Builders and Developers, 594, V Main, 11th Cross, Sadashiva Nagar, Bangalore, is no longer necessary.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby declares that the said Commission shall cease to exist and Shri Justice Kuldip Singh shall cease to hold the office of the Member of the said Commission on 26-6-90.

[No. 415/8/89-AVD-IV]

D. P. BAGCHI, Jt. Secy.

